

हरियाणा राज्य, आदि। सावित्री देवी और अन्य, (सूरी, जे।

अपीलीय सिविल

पी. सी. पंडित और सी. जी. सूरी, जे.जे के समक्ष

हरियाणा राज्य, आदि, *अपीलकर्ता*

बनाम

सावित्री देवी और अन्य- उत्तरदाता

1972 का आर.एस.ए. नंबर 669।

4 दिसंबर, 1973।

पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम (1948 का 46) - धारा 19 - बिक्री कर अधिकारियों द्वारा किए गए मूल्यांकन आदेश - ऐसे आदेशों पर सवाल उठाने के लिए सिविल न्यायालयों का अधिकार - क्या बेदखल किया गया है - प्रासंगिक साक्ष्य के आधार पर अनुमान या निष्कर्ष - क्या कर निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 के तहत किए गए मूल्यांकन के आधार पर मांगे गए कर की राशि का भुगतान करने का कर्तव्य बनता है और अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान की गई मशीनरी के उपयोग के अलावा मूल्यांकन पर सवाल उठाने का अधिकार क्षेत्र, मूल्यांकन के आधार पर उत्पन्न होने वाले भुगतान के वैधानिक दायित्वों के साथ असंगत है। जब कोई कानून विशेष न्यायाधिकरण के आदेशों को अंतिम रूप देता है तो दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा जाना चाहिए यदि ऐसा करने के लिए पर्याप्त उपाय है जो दीवानी अदालतें आम तौर पर एक मुकदमे में करती हैं। हालांकि, ऐसे प्रावधान उन मामलों को बाहर नहीं करते हैं जहां विशेष अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है या वैधानिक न्यायाधिकरण ने न्यायिक प्रक्रिया के मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य नहीं किया है। यह सामान्य प्रक्रिया से भटकने वाला या प्रक्रिया की अनियमितता नहीं है, चाहे वह कितना ही धिनौना या अप्रासंगिक हो, जिसे किसी भी मौलिक सिद्धांतों के साथ गैर-अनुरूपता के रूप में वर्णित किया जा सकता है ताकि विशेष न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से वंचित किया जा सके

हरियाणा राज्य, आदि। सावित्री देवी और अन्य, (सूरी, जे।

या उसके आदेश को गैर-स्थायी बना दिया जा सके। जहां न्यायालय के क्षेत्राधिकार की स्पष्ट सीमा है, वहां प्रदान किए गए उपायों की पर्याप्तता का पता लगाने के लिए विशेष अधिनियम की स्कीम की जांच प्रासंगिक हो सकती है लेकिन सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बनाए रखने के लिए निर्णायक नहीं है। अधिनियम में पीड़ित पक्ष के लिए उपलब्ध उपायों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं और इसलिए सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को अधिनियम के तहत बिक्री कर प्राधिकरणों द्वारा किए गए मूल्यांकन आदेश पर सवाल उठाने से रोक दिया गया है।

अभिनिर्धारित किया गया कि परिस्थितिसंबंधी साक्ष्य कुछ और नहीं बल्कि अनुमानों की एक श्रृंखला है, जो मानव आचरण के सामान्य पाठ्यक्रम और कारण और प्रभाव के प्राकृतिक अनुक्रमों को ध्यान में रखते हुए, वैध रूप से मामलों की सिद्ध स्थिति से तैयार किया जा सकता है। इसलिए आकलन प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक साक्ष्य के आधार पर अनुमान या निष्कर्ष वैध रूप से निकाले जा सकते हैं।

बढ़ी हुई अपीलीय शक्तियों के साथ श्री एस.एन. प्रकाश, वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, हिसार के न्यायालय के दिनांक 9 जून, 1971 के आदेश से नियमित द्वितीय अपील, श्री एच. सी. गुप्ता, उप-न्यायाधीश, द्वितीय श्रेणी की लागत के साथ पुष्टि करते हुए, हिसार, दिनांक 4 नवंबर, 1968, ने वादी के मुकदमे का फैसला सुनाया और आगे आदेश दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को प्रतिवादी फर्म नंबर 3 से 5 पर वादी की ओर से लगाए गए 2,17,960 रुपये की कर राशि वसूलने से रोका जाए और पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया।

अपीलकर्ताओं की ओर से हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता सी. डी. दीवान और अधिवक्ता एस. पी. जैन उपस्थित।

डी.एन.अवस्थी, वकील, उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

सूरी, जे -1971 के दस बिक्री कर संदर्भ संख्या 20 से 29, 19 फरवरी, 1973 को प्रथम खंडपीठ के समक्ष आए और उन्हें 1972 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 669 के साथ सुनवाई करने का निर्देश दिया गया। इस प्रकार ये सभी

हरियाणा राज्य, आदि। सावित्री देवी और अन्य, (सूरी, जे।

मामले हमारे समक्ष रखे गए और एक साथ सुने गए। इन्हें किसी भी संबंधित पक्ष के पूर्वाग्रह के बिना एक निर्णय द्वारा आसानी से निपटाया जा सकता है।

- (2) दिनांक 29 जून, 1966 को जिले के आबकारी और कराधान अधिकारी की देखरेख में बिक्री कर विभाग के कर्मचारियों द्वारा हिसार की एक दुकान पर छापा मारा गया और निरीक्षण किया गया। परिसर में मौजूद श्री बुध राम दुकान के अंदर पड़ी बही-खातों में कई प्रविष्टियों की व्याख्या नहीं कर सके और इसलिए इन पुस्तकों को श्री बुध राम को दी गई एक स्पष्ट रसीद के आधार पर कब्जे में ले लिया गया और उन्हें 1 जुलाई, 1966 को कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निदेश दिया गया। वह उक्त तारीख को उपस्थित होने में विफल रहे और पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 11 (6) के तहत (इसके बाद इसे केंद्रीय सामान्य बिक्री कर अधिनियम जिसे बाद में 'केंद्रीय अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, से अलग करने के लिए संक्षेप में 'राज्य अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया,) के तहत उन्हें नोटिस जारी किए गए। श्री बुध राम ने, दो चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए, 5 जुलाई, 1966 को मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष 4 जुलाई, 1966 दिनांकित एक आवेदन दिया, जिस पर मेसर्स बुध राम देसी घी स्टोर के मालिक के रूप में उनके हस्ताक्षर थे। श्री बुध राम ने दो चार्टर्ड अकाउंटेंटों के प्रतिनिधित्व में 4 जुलाई, 1966 को मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर उन्होंने मेसर्स बुद्ध राम देसी घी स्टोर के मालिक (*मलिक*) के रूप में हस्ताक्षर किए। आवेदन में उनके 1 तारीख को उपस्थित न होने का कोई कारण नहीं बताया गया था और प्रार्थना की गई थी कि उनकी उपस्थिति में लेखा पुस्तकों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। श्री बुध राम को घी कारोबार से संबंधित चालू खाते की पासबुक और पिछले वर्षों के खाते की किताबें पेश करने का निर्देश दिया गया था जो दुकान के अंदर नहीं मिली थीं। कुछ दिनों बाद दिए गए एक अन्य आवेदन में, श्री बुध राम ने अपने मामा, गिरधारी लाल पुत्र रघुनाथ राय की विधवा श्रीमती रुक्मणी देवी को मेसर्स बुध राम देसी घी स्टोर का मालिक बताया, जबकि उन्होंने दावा किया कि वह मेसर्स भीम राज बुध राम के नाम और शैली के तहत अपना व्यवसाय कर रहे थे। कुछ साझेदारी विलेख प्रस्तुत किए

हरियाणा राज्य, आदि। सावित्री देवी और अन्य, (सूरी, जे।

गए थे, लेकिन चूंकि इन फर्मों को भारतीय भागीदारी अधिनियम या राज्य या केंद्रीय बिक्री कर अधिनियमों के तहत पंजीकृत करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था, इसलिए यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि ये विलेख केवल कागजी लेनदेन नहीं थे या इन पर कार्रवाई की गई थी। ऊपर उल्लिखित दो फर्म नामों के अलावा, न केवल दुकान के बाहर एक उत्कीर्ण पत्थर की गोली पर बल्कि दुकान के अंदर से कब्जे में लिए गए कई दस्तावेजों और पुस्तकों में "मेसर्स गिरधारी लाल रघुनाथ राय" नामक एक अन्य फर्म का उल्लेख था। श्री बुध राम से पूछताछ और बही-खातों तथा अन्य दस्तावेजों में प्रविष्टियों के आधार पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने 17/18 अगस्त, 1966 को रुक्मणी देवी और बुध राम की दो पारिवारिक शाखाओं के कतिपय अन्य सदस्यों की उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किए, जो दुकान में किए जा रहे घी के कारोबार से जुड़े प्रतीत होते थे। उक्त व्यक्तियों के संघ में रुक्मणी देवी की तीन पुत्रियाँ या उनके पति और इनमें से एक पुत्री का पुत्र शामिल था जिसे श्रीमती रुक्मणी देवी ने गोद लिया था। श्री बुध राम के बेटे और बहू जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे, उन्हें 20 अगस्त, 1966 को मूल्यांकन प्राधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए इसी तरह के नोटिस भेजे गए थे। श्री रुक्मणी देवी का एक दामाद उक्त तिथि को उपस्थित हुआ और कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उसकी जांच की गई। जिन अन्य व्यक्तियों को नोटिस भेजे गए थे, उनमें से कई वकील के माध्यम से पेश हुए, जिन्होंने वादा किया कि उनके ग्राहकों को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश किया जाएगा। तदनुसार मामले को 23 अगस्त, 1966 और फिर 25 अगस्त, 1966 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन पीठासीन अधिकारी इन दोनों तिथियों पर रुग्ण अवकाश पर थे। करदाताओं ने एक आवेदन दायर किया था जो 27 अगस्त, 1966 को पीठासीन अधिकारी के समक्ष आया और मामले को 29 अगस्त, 1966 तक के लिए स्थगित कर दिया गया जब निर्धारिती और व्यक्तियों के संदिग्ध संघ के सदस्यों के वकील उपस्थित थे। इस आवेदन में अनुरोध किया गया था कि करदाता को राज्य अधिनियम की धारा 10 (2) के तहत निपटान के लिए आवेदन करने के लिए समय दिया जा सकता है। आवेदन को इस आधार पर

हरियाणा राज्य, आदि। सावित्री देवी और अन्य, (सूरी, जे।

खारिज कर दिया गया था कि यह देर से किया गया था और कार्यवाही में देरी करने का प्रयास था क्योंकि खाता पुस्तिकाओं की वापसी की अंतिम तिथि निकट आ रही थी। ये व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से पेश होने में विफल रहे थे, लेकिन उनके वकील ने हलफनामा दायर किया था, जिसमें सभी

उपर्युक्त फर्मों के साथ संबंध से इनकार कर दिया गया था और सबूत पेश करने के लिए और समय मांगा गया था। एसोसिएशन के इन सदस्यों के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफलता के कारण, 30 अगस्त, 1966 को उन सभी के खिलाफ मूल्यांकन आदेश पारित किए गए थे। ये आदेश आकलन वर्ष 1962-63 से 1966-67 से संबंधित हैं। चूंकि पुस्तकों में प्रविष्टियों और बुध राम द्वारा दिए गए बयान से पता चलता है कि इन वर्षों के दौरान अंतर-राज्यीय लेनदेन भी चल रहे थे, इनमें से कुछ वर्षों के लिए केंद्रीय अधिनियम के तहत सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन किए गए थे, जिनके लिए करदाताओं द्वारा खाता पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई गई थीं। राज्य अधिनियम और केंद्रीय अधिनियम के तहत बिक्री कर और जुर्माने के रूप में व्यक्तियों के इस संघ पर लगभग 2,18,000 रुपये की कुल देयता लगाई गई है। करदाता इन अधिनियमों के तहत उच्च न्यायालय में अपील और संदर्भों के अपने उपायों के साथ-साथ उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करने और हिसार में अधीनस्थ सिविल न्यायालय में एक नियमित मुकदमा दायर करने का सहारा ले रहे हैं। 1966 की सिविल रिट संख्या 2056 24 सितंबर, 1966 को उच्च न्यायालय में दायर की गई थी और मोशन बेंच ने याचिका को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा विवाद में राशि के संबंध में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के अधीन वसूली पर रोक लगा दी थी। यद्यपि हिसार के उप न्यायाधीश के ध्यान में यह लाया गया था, जिन्होंने दीवानी वाद की सुनवाई की थी, कि रिट याचिका अभी भी लंबित है और उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों पर अंतरिम राहत प्रदान की थी, उप-न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ-साथ, उप न्यायाधीश ने बिना किसी आपत्ति के स्थायी आधार पर सर्वव्यापी राहत प्रदान की थी, अन्य बातों के साथ-साथ, बिक्री कर अधिकारियों द्वारा उठाया गया मूल्यांकन और मांग अधिकार क्षेत्र के बिना थी। अपील पर वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए उप-न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री की पुष्टि की थी कि इस बात का रत्ती भर भी साक्ष्य नहीं है कि वादी किसी भी तरह से उस व्यवसाय से जुड़े थे जिसमें बिक्री कर अधिकारियों ने मूल्यांकन और मांग को सही ठहराते हुए कर योग्य कारोबार पाया था। वादी ने स्पष्ट रूप से सिविल मुकदमे को अधिक सुविधाजनक या व्यवहार्य पाया, भले ही यह सस्ता न हो, मूल्यांकन को चुनौती देने वाले वाद पर भुगतान किए गए मामूली अदालत शुल्क के बावजूद और कुछ लाख रुपये की राशि की मांग के बावजूद, यह भी देखा जा सकता है कि बुध राम और रुक्मणी देवी उच्च न्यायालय में मूल्यांकन और मांग को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर करने में वादी के साथ शामिल हो गए थे, लेकिन

उन्हें केवल करदाता फर्मों के मालिक या प्रतिनिधि के रूप में दिखाया गया था, जिन्हें सिविल मुकदमे में प्रतिवादी नंबर 3 से 5 के रूप में शामिल किया गया था। इस बीच, अगस्त 1966 की शुरुआत में, कहा जाता है कि बुध राम और रुक्मणी देवी ने ऐसी परिस्थितियों में अपनी अचल संपत्ति का हस्तांतरण अपने रिश्तेदारों के पक्ष में कर दिया था, जो दृढ़ता से सुझाव देते हैं कि यह संपत्ति को बकाया सेल्स टैक्स और पेनल्टी की मांग की संतुष्टि में जब्त होने से बचाने का एक प्रयास था।

हरियाणा राज्य, आदि। सावित्री देवी और अन्य, (सूरी, जे।

परिवार के सदस्यों, जो बिना किसी प्रतिफल के संपत्ति के हस्तांतरणकर्ता थे, के बिक्री कर अधिकारियों द्वारा उन व्यक्तियों के संघ में शामिल करना, जिन्हें घी व्यवसाय के डीलरों या निर्धारितियों के रूप में माना जाता है, इस उपकरण के उद्देश्य को विफल कर देगा।

(3) अधीनस्थ सिविल न्यायालयों के निर्णयों और डिक्री के खिलाफ नियमित दूसरी अपील दायर की गई थी और यह सवाल उठाया गया था, जो अक्सर उठता है, कि एक विशेष न्यायाधिकरण बनाने वाला अधिनियम एक स्पष्ट प्रावधान द्वारा सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को किस हद तक बाहर कर सकता है या निहित रूप से पीड़ित पक्ष को उन उपायों के साथ प्रदान कर सकता है जो आम तौर पर सिविल मुकदमे में मांगे जा सकते हैं। इस विषय पर भारत में विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई निर्णय हैं और लाहौर उच्च न्यायालय की विभिन्न पूर्ण पीठों के दो निर्णय नगरपालिका *समिति, मोंटगोमरी बनाम मास्टर संतसिंह* (1) और *लछमन सिंह बनाम नथा सिंह और अन्य* (2) को हमारे सामने उद्धृत किया गया है। तथापि, यह मामला बाद के कई निर्णयों में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति, भारत के संघीय न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सहित देश के सर्वोच्च न्यायालयों के विचाराधीन रहा है और मैं अपनी चर्चा इन उच्चतम न्यायालयों के आदेशों तक ही सीमित रखूंगा। पिछले कुछ दशकों में विकसित हुए इस विचार की उत्पत्ति राज्य सचिव बनाम *मास्क एंड कंपनी* (3) के मामले में प्रिवी काउंसिल के निर्णय द्वारा प्रस्तुत की गई थी। न्यायिक समिति के लिए निर्णय लिखने वाले लॉर्ड थंकर्टन ने अन्य बातों के अलावा, कहा था कि सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह के बहिष्करण को या तो स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए या स्पष्ट रूप से निहित किया जाना चाहिए।

- (1) ए.आई.आर. 1940 लाह। 377 (एफ.बी.)
- (2) ए.आई.आर. 1940 लाह। 401 (एफ.बी.)
- (3) ए.आई.आर. 1940 पी.सी. 105=67 आई.ए. 222.

यहां तक कि अगर अधिकार क्षेत्र को इस तरह से बाहर रखा गया था, तो सिविल न्यायालयों के पास उन मामलों की जांच करने का अधिकार है जहां अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था या विशेष न्यायाधिकरण ने न्यायिक प्रक्रिया के मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य नहीं किया था। मास्क एंड कंपनी, जो एक उप न्यायाधीश की अदालत में दायर मुकदमे में वादी थे, ब्रिटिश भारत के बाहर से आयातित सुपारी की खेप पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा लगाए गए शुल्क का भुगतान करने के अपने दायित्व का विरोध कर रहे थे। शुल्क लगाने की शक्तियों को समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के कुछ प्रावधानों के साथ पढ़े गए भूमि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत लागू किया गया था। इन अधिनियमों में अपील दायर करने और उन्हें एक पुनरीक्षण याचिका दायर करने का प्रावधान किया गया था, हालांकि केवल कार्यकारी अधिकारियों के लिए। अंतिम रूप से सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को रोकने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था।

कार्यकारी अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों से संलग्न करने की मांग की गई थी। अधिनियम में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था जो पार्टी को सिविल न्यायालयों में किसी भी उपाय की मांग करने या इस तरह के अधिकार को रोकने का अधिकार देता हो। विशेष अधिनियमों में ऐसे प्रावधान पाए गए जो विशेष कानून द्वारा बनाए गए दायित्वों के संबंध में एक पूर्ण और स्व-निहित संहिता थे और इसने अपील को कार्यकारी सरकार के सर्वोच्च प्रमुख तक ले जाने में सक्षम बनाया। प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के लॉर्डशिप को यह समझना मुश्किल था कि सिविल मुकदमे के माध्यम से चुनौती के अलावा कार्यकारी अधिकारियों के आदेश को और क्या चुनौती देने का इरादा था। भले ही उच्च न्यायालय ने एक अपील पर ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि इन प्रावधानों ने सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के लिए एक निहित बाधा पैदा की है, प्रिवी काउंसिल के उनके लॉर्डशिप ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और उप न्यायाधीश के फैसले को बहाल कर दिया। यह टिप्पणी कि सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए, इसका मतलब यह नहीं लिया जा सकता है कि इस तरह के बहिष्करण को शायद ही कभी या शायद ही कभी निहित किया जाना है।

(4) प्रिवी काउंसिल का अगला फैसला, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बाद के कई फैसलों में चर्चा का विषय रहा है, रैले इन्वेस्टमेंट कंपनी *लिमिटेड बनाम काउंसिल में गवर्नर-जनरल (4)* के मामले में था। यह (भारतीय) आयकर अधिनियम, 1922 के तहत एक मामला था। उस अधिनियम की धारा 67 ने इस अधिनियम के तहत किए गए मूल्यांकन को रद्द करने या संशोधित करने के लिए किसी भी सिविल मुकदमे को दायर करने के लिए एक स्पष्ट रोक बनाई। यद्यपि इस अधिनियम के कर प्रावधान (धारा 45)

हरियाणा राज्य, आदि। सावित्री देवी और अन्य, (सूरी, जे।

की वैधता को चुनौती दी गई थी, फिर भी यह देखा गया कि अधिनियम के तहत किए गए मूल्यांकन के आधार पर मांगे गए कर की राशि का भुगतान करने का कर्तव्य और अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान की गई मशीनरी के उपयोग के बजाय मूल्यांकन पर सवाल उठाने

(4) ए.आई.आर. 1947 पी.सी. 78=74 आई.ए.

का अधिकार क्षेत्र अधिनियम के आधार पर उत्पन्न होने वाले भुगतान के वैधानिक दायित्वों के साथ असंगत प्रतीत होगा। मूल्यांकन। लॉर्डशिप के मन में एकमात्र संदेह यह था कि क्या मूल्यांकन को रद्द करने या संशोधित करने के लिए सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने के लिए एक स्पष्ट प्रावधान आवश्यक था। यहां फिर से कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने अपने सामान्य मूल क्षेत्राधिकार में आयकर अधिनियम की धारा 67 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 226 को अधिकारातीत माना था और मुकदमे का फैसला सुनाया लेकिन संघीय न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया था और प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति द्वारा अपील पर संघीय न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया था।

(5) ऊपर उल्लिखित दो निर्णयों में प्रिवी काउंसिल के आदेश को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बाद के कई निर्णयों में इसका पालन किया गया था, जब तक कि *फर्म ऑफ इलूरी सुब्बय्या चेट्टी एंड संस बनाम आंध्र प्रदेश राज्य* (5) के मामले में उनकी शुद्धता के बारे में कुछ संदेह व्यक्त नहीं किए गए थे। इन संदेहों का संदर्भ तब *कस्टोडियन, इवैक्यूई प्रॉपर्टी, पंजाब और अन्य बनाम जाफरान बेगम* (6) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पृष्ठ 174 पर पैराग्राफ 12 के अंत में दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच जिसमें हिदायतुल्लाह, सी.जे शामिल थे, जिन्होंने धुलाबाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य (7) में बेंच के लिए फैसला लिखा था ने तब टिप्पणी की कि पहले उल्लिखित दो प्रिवी काउंसिल निर्णयों के अनुपात की शुद्धता के संबंध में न्यायालय की राय कैसे डगमगा रही थी (पृष्ठ 81 पर पैराग्राफ 9 के अंत तक)। हालांकि, इस फैसले में पूरे मामले के कानून और मास्क एंड कंपनी (3) और रैले निवेश कंपनी (4) के मामलों में प्रिवी काउंसिल के आदेश की शुद्धता पर चर्चा की गई थी की पुनः पुष्टि की गई थी।

(5) ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 322.

(6) ए.आई.आर. 1968 एस.सी. 169.

(7) ए.आई.आर. 1969 एस.सी.

पृष्ठ 89 और 90 पर निर्णय के पैराग्राफ 32 में निम्नलिखित अंतिम निष्कर्ष इस प्रकार बताए गए थे:

- (एक) "जहां क़ानून विशेष न्यायाधिकरणों के आदेशों को अंतिम रूप देता है, सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा जाना चाहिए यदि ऐसा करने के लिए पर्याप्त उपाय है जो सिविल अदालतें सामान्य रूप से एक मुकदमे में करती हैं। तथापि, इस प्रकार के प्रावधान उन मामलों को बाहर नहीं करते हैं जिनमें किसी विशेष अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है अथवा सांविधिक अधिकरण ने न्यायिक प्रक्रिया के मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य नहीं किया है।
- (दो) जहां न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट सीमा है, वहां प्रदान किए गए उपायों की पर्याप्तता का पता लगाने के लिए विशेष अधिनियम की योजना की जांच प्रासंगिक हो सकती है लेकिन सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बनाए रखने के लिए निर्णायक नहीं है।
- जहां स्पष्ट बहिष्करण नहीं है, वहां इरादे का पता लगाने के लिए उपायों और विशेष अधिनियम की योजना की जांच आवश्यक हो जाती है और जांच का परिणाम निर्णायक हो सकता है। बाद के मामले में यह देखना आवश्यक है कि क्या क़ानून एक विशेष अधिकार या दायित्व बनाता है और अधिकार या देयता के निर्धारण का प्रावधान करता है और इसके अलावा यह निर्धारित किया गया है कि उक्त अधिकार और दायित्व के बारे में सभी प्रश्न इस प्रकार गठित न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, और क्या सिविल न्यायालयों में कार्यों से जुड़े उपचार सामान्य रूप से उक्त क़ानून द्वारा निर्धारित किए गए हैं या नहीं।
- (तीन) किसी अधिनियम विशेष के उपबंधों को *अधिकार-विहीन मानते हुए चुनौती* को उस अधिनियम के अंतर्गत गठित अधिकरणों के समक्ष नहीं लाया जा सकता है। यहां तक कि उच्च न्यायालय भी अधिकरणों के निर्णय से संशोधन या संदर्भ के संबंध में उस प्रश्न पर विचार नहीं कर सकता है।
- (चार) जब किसी प्रावधान को पहले ही असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है या किसी प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती दी जाती है, तो मुकदमा खुला होता है। यदि दावा स्पष्ट रूप से परिसीमा अधिनियम द्वारा निर्धारित समय के भीतर है, तो प्रमाण पत्र की रिट में रिफंड के लिए एक निर्देश शामिल हो सकता है, लेकिन यह मुकदमे को बदलने के लिए एक अनिवार्य उपाय नहीं है।

हरियाणा राज्य, आदि। सावित्री देवी और अन्य, (सूरी, जे।

- (पाँच) जहां विशेष अधिनियम में संवैधानिक सीमाओं से अधिक एकत्र किए गए या अवैध रूप से एकत्र किए गए कर की वापसी के लिए कोई तंत्र नहीं है।
- (छः) इसकी संवैधानिकता के अलावा मूल्यांकन की शुद्धता के प्रश्न अधिकारियों के निर्णय के लिए हैं और एक सिविल मुकदमा तब नहीं होता है जब अधिकारियों के आदेशों को अंतिम घोषित किया जाता है या विशेष अधिनियम में एक स्पष्ट निषेध है। किसी भी मामले में विशेष अधिनियम की योजना की जांच की जानी चाहिए क्योंकि यह एक प्रासंगिक जांच है।
- (सात) सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण का अनुमान आसानी से नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि ऊपर निर्धारित शर्तें लागू न हों।

(6) हरियाणा राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री दीवान उस समय एक संविधि के उपबंधों के बीच अंतर करना चाहते थे जो एक विशेष अधिकरण के आदेशों को अंतिम रूप देते हैं और ऐसे मामले जिनमें सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट अवरोध बनाया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि 'उपरोक्त निष्कर्ष संख्या 1 विशेष न्यायाधिकरण के आदेशों से जुड़े अंतिम रूप के मामलों में लागू होगा, जबकि निष्कर्ष संख्या 2 केवल उन मामलों में लागू होगा जहां इस तरह के अधिकार क्षेत्र के लिए एक एक्सप्रेस बार बनाया गया था। मुझे डर है कि मैं उस अंतर को ठीक से समझ नहीं सका जो श्री दीवान ने करना चाहा था क्योंकि मेरे विचार से सभी मामलों में महत्वपूर्ण परीक्षा यह होगी कि क्या वैधानिक न्यायाधिकरण का निर्माण करने वाले विशेष अधिनियम ने कानून द्वारा बनाए गए विशेष दायित्व से पीड़ित पक्ष के लिए उपचार के लिए पर्याप्त प्रावधान किया था या नहीं। मेरे विचार से सभी मामले यह होंगे कि वैधानिक अधिकरण का सृजन करने वाले विशेष अधिनियम में संविधि द्वारा सृजित विशेष दायित्व से पीड़ित पक्ष के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए थे या नहीं। मेरी बात को केरल राज्य बनाम मैसर्स राम- स्वामी अय्यर एंड संस (8) के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में स्पष्ट किया जा सकता है। इस मामले में, आक्षेपित मूल्यांकन के समय, विशेष अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो मुकदमा दायर करने या विशेष न्यायाधिकरणों के आदेशों को अंतिम रूप देने पर रोक लगाता हो। अधिनियम की योजना में प्रदान किए गए उपायों की पर्याप्तता के कारण विशेष अधिनियम की पंक्तियों के बीच एक निहित सीमा पढ़ी गई थी। रैले निवेश कंपनी (4) (सुप्रा), के मामले में लॉर्ड उथवाट, जिन्होंने प्रिवी काउंसिल के लिए निर्णय लिखा था, के मन में संदेह था कि क्या सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने के लिए एक स्पष्ट प्रावधान आवश्यक था, जहां आयकर अधिनियम के तहत एक मूल्यांकन को रद्द करने या संशोधित करने की मांग की गई थी।

(8) ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 1738=XVIII एस.टी.सी. 1 (एस.सी.)

(7) उपर्युक्त चर्चा *किए गए निर्णयों के अनुपात* में, नीचे दिए गए सिविल न्यायालयों के आदेशों और आदेशों को बनाए नहीं रखा जा सकता है। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ये न्यायालय किसी निर्णय पर पहुंचने में इतने लापरवाह रहे हों कि उन्होंने दो बिक्री कर अधिनियमों के प्रावधानों को देखने या उस सामग्री की जांच करने की भी परवाह नहीं की जिस पर 30 अगस्त, 1966 के आक्षेपित मूल्यांकन आदेश आधारित थे) हालांकि उन आदेशों की प्रमाणित प्रतियां रिकॉर्ड पर रखी गई थीं और डी 3 से डी 7 के रूप में चिह्नित की गई थीं। ट्रायल जज ने सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र को हटाने से संबंधित मुद्दे संख्या 1 की चर्चा के दौरान चार अलग-अलग स्थानों पर प्रासंगिक प्रावधान के रूप में धारा 19 के बजाय धारा 9 का गलत उल्लेख किया है। इस चर्चा के दौरान कहीं भी सही खंड का उल्लेख नहीं किया गया है जो यह दिखा सकता है कि यह केवल लिपिकीय त्रुटि नहीं थी - निरीक्षण के कारण। निचली अपीलीय अदालत ने पालतू जानवरों की अभिव्यक्ति का उपयोग करने की उत्सुकता में कहा है कि यह साबित करने के लिए रत्ती भर भी सबूत नहीं है कि वादी आकलन के तहत घी के कारोबार से जुड़े थे। उन्होंने उन तथ्यों, परिस्थितियों और सबूतों के अस्तित्व को नजरअंदाज करने का विकल्प चुना है जो बहुत अधिक थे और जिनका इन वादियों से देय कर की पात्रता के सवाल पर सीधा असर पड़ा था। *रैले इन्वेस्टमेंट कंपनी (4) (सुप्रा)* में प्रिवी काउंसिल द्वारा यह माना गया था कि अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए देयता निर्धारित करने का कर्तव्य विशेष टिब्यूनल का था और इस मामले में सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगा दी गई थी। *मास्क & कंपनी के मामले (3) (सुप्रा)*, सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने के मामले को अधिनियम में केवल इसलिए पढ़ा गया क्योंकि पीड़ित पक्ष के पास केवल कार्यकारी अधिकारियों के लिए ही उपाय उपलब्ध थे। यह निर्णय उस समय दिया गया था जब पीड़ित पक्ष को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में कोई रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32, 226 और 227 के अनुरूप कोई प्रावधान कानून की पुस्तक पर मौजूद नहीं था। वादी सहित निर्धारितियों के विद्वान वकील श्री अवस्थी का यह मामला नहीं है कि राज्य या केंद्रीय अधिनियम विशेष न्यायाधिकरणों के आदेशों से असंतुष्ट पक्ष के लिए पर्याप्त उपायों का प्रावधान नहीं करते हैं। राज्य अधिनियम की धारा 11 एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करती है कि मूल्यांकन कैसे किया जाना है। करदाता के पास सबूत पेश करने और अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर था। धारा 20 और 21 में अपील दायर करने और संशोधन करने का प्रावधान है। धारा 22 तब करदाता को कानून के प्रश्न को उच्च न्यायालय को संदर्भित करने का

हरियाणा राज्य, आदि। सावित्री देवी और अन्य, (सूरी, जे।

अधिकार देती है और यदि बिक्री कर अधिकारी संदर्भ देने से इनकार करते हैं, तो वह एक जनादेश के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है जो वास्तव में राज्य अधिनियम की धारा 22 (2) के तहत उनके आवेदन पर वादी सहित करदाताओं को दिया गया है। ये धाराएं जो पीड़ित पक्ष के लिए उपलब्ध उपायों के लिए पर्याप्त प्रावधान करती हैं, सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में एक अंतर्निहित बाधा पैदा करेंगी, भले ही धारा 19 राज्य अधिनियम में न हो।

(8) श्री श्रीवास्तव अपने इस तर्क के समर्थन में किसी भी प्रत्यक्ष लेखक का हवाला नहीं दे पाए कि अधिनियम के तहत कर के रूप में जो आकलन किया गया है वह एक लेनदेन या सौदा है, न कि व्यक्ति या डीलर। *श्री अवस्थी द्वारा उद्धृत* भारत संघ बनाम *श्री मोती राम मेहरा* (9) मामले में इस न्यायालय की एकल पीठ का निर्णय और खजान सिंह और एक अन्य *दलीप सिंह और एक अन्य* (10) मामले में खंडपीठ के फैसले का वर्तमान मामले के तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं है। श्री अवस्थी के तर्क को यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो इसके कुछ बहुत ही विचित्र परिणाम हो सकते हैं। आइए हम उस मामले की कल्पना करें जब एक आयकर या सेल्स-टैक्स इंस्पेक्टर एक दुकान पर छापा मारता है, जिसके सामने के दरवाजे बंद होते हैं और उसके मुखौटे पर "मेसर्स बोगस स्लीमैन एंड एसोसिएट्स, कमीशन एजेंट" का साइन-बोर्ड होता है। आगे का सौदा करने वाली ऐसी किसी भी फर्म के परिसर में कोई स्टॉक-इन-ट्रेड

(9) 1972 के सीआर नंबर 708 पर 7 फरवरी, 1973 को फैसला किया गया।

(10) 1969 रेव एल.आर.

नहीं होगा क्योंकि इस तरह के लेनदेन में कोई भौतिक या तैयार डिलीवरी नहीं होती है। कोई गुप्त पिछला दरवाजा हो सकता है जिससे डीलर परिसर में प्रवेश कर सके और मुख्य रूप से टेलीफोन पर कारोबार कर सके। दैनिक मेल प्राप्त करने के लिए दीवार या दरवाजे में एक लेटर-बॉक्स का छेद हो सकता है। खाता पुस्तिकाएं दुकान पर पाई जा सकती हैं और कराधान अधिकारियों को कर योग्य कारोबार निर्धारित करने और देय कर का आकलन करने में सक्षम बना सकती हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि, इसी तरह की स्थिति में, कराधान अधिकारी देय कर की वसूली के विचार के साथ व्यवसाय करने वाले व्यक्ति की पहचान का पता लगाने के लिए कदम नहीं उठा सकते हैं। परिसर के पट्टे के अधिकार, टेलीफोन कनेक्शन और खाता पुस्तिकाएं खुले बाजार में बेचे जाने पर बकाया राशि की संतुष्टि

के लिए शायद ही पर्याप्त होंगी; भले ही यह कहा जा सके कि ये संपत्तियां कानूनी रूप से हस्तांतरणीय थीं। श्री अवस्थी के तर्क का अर्थ यह होगा कि कराधान प्राधिकारी ऐसी आकस्मिक स्थिति में कर और जुर्माने आदि की बकाया राशि की कोई वसूली करने में असहाय होंगे। डीलर कौन है और इसका गठन क्या है और व्यवसाय में रुचि रखने वाले या जुड़े व्यक्ति कौन हैं, चाहे भागीदार के रूप में या अन्यथा, ये ऐसे मामले हैं जिन पर कर के मूल्यांकन को पूरा करने और कार्यवाही में उठाई जा सकने वाली मांगों की प्राप्ति के लिए जांच की जानी है। भले ही व्यक्तियों के संगठन के संविधान के निर्धारण को मूल्यांकन जांच के लिए एक तथ्य संपार्श्विक के रूप में वर्णित किया गया हो, मामले को निम्न न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना होगा, यहां तक कि *मैसर्स कमला मिल्स लिमिटेड बनाम बम्बई राज्य (11)* में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्सों के अनुसार भी। जिसका उल्लेख श्री अवस्थी ने किया है। इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि लेन-देन की प्रकृति के प्रश्न का निर्णय भी हीन या विशेष न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना है। धारा 2 के खंड (डी) में परिभाषित 'डीलर'

(11) ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 1942.

और राज्य अधिनियम की धारा 6 के तहत जांच के दौरान उत्पन्न होने वाले अन्य सभी मामलों का निर्णय *केरल राज्य बनाम एन. रामास्वामी अय्यर एंड संस (8)* सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बिक्री कर अधिकारियों द्वारा किया जाना है। यह निर्धारित किए बिना संभवतः एक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है कि वह व्यक्ति या पक्ष कौन है जिसे कर की पात्रता के लिए मूल्यांकन किया जाना है। श्री दीवान ने इस संबंध में *मद्रास राज्य बनाम श्री रामकृष्ण मिल्स (कोयम्बटूर) लिमिटेड (12)* और *के. बर्मन बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, कलकत्ता और अन्य (13)* में मद्रास और मैसूर उच्च न्यायालयों की खंड पीठों के दो निर्णयों का भी उल्लेख किया है। फिर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं जो दिखाते हैं कि संविधान व्यक्तियों के संघ के रूप में वर्णित एक समूह होना चाहिए

(12) (1969) 24 एस.टी.सी. 274.

(13) (1971) 28 एस.टी.सी. 637.

विशेष न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित। इस संबंध में *आयकर आयुक्त, पूना बनाम बुलढाणा जिला मुख्य कपड़ा आयातक समूह (14)*, *मोहम्मद नूरुल्ला बनाम आयकर आयुक्त, मद्रास (15)* और *आयकर आयुक्त, बॉम्बे उत्तर, कच्छ और सौराष्ट्र, अहमदाबाद बनाम श्रीमती इंदिरा बालकृष्ण (16)* का हवाला दिया गया है। व्यक्तियों के उक्त संघ या इसके गठन के संबंध में विशेष अधिकरण के तथ्यों के निष्कर्षों को सिविल न्यायालय में चुनौती या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

(9) वरिष्ठ उप न्यायाधीश, हिसार ने राज्य द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए टिप्पणी की थी कि इस बात

(14) ए.आई.आर.1961एस.सी.1261=42 आई.टी.आर. 172.

(15) ए.आई.आर.1961एस.सी.1043=42 आई.टी.आर. 115.

(16) ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 1172=39 आई.टी.आर. 546.

का ज़रा भी सबूत नहीं है कि वादी हिसार में चल रहे घी के कारोबार से जुड़े थे। उनकी राय में, आकलन प्राधिकरण के निष्कर्ष केवल खातों की पुस्तकों में प्रविष्टियों पर आधारित थे जैसे कि ये प्रविष्टियां कोई सबूत नहीं थीं। उन्होंने यह देखने की परवाह नहीं की कि उन प्रविष्टियों की प्रकृति क्या थी या वे वास्तव में हुए लेनदेन का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितनी वास्तविक थीं। उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख किया था कि करदाता ने कुछ साझेदारी दस्तावेज पेश किए थे। हालांकि, उन्होंने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि, दस्तावेजों के अनुसार, वादियों में से एक हिसार में इस घी के कारोबार में भागीदार था, जब तक कि श्रीमती रुक्मणी देवी ने उसकी जगह नहीं ले ली थी। यदि उन्होंने मूल्यांकन आदेशों की प्रतियां पढ़ी होतीं, तो उन्हें पता चलता कि वादी में से एक ने हिसार के एक बैंक में चालू खाता खोला था और यह कि प्रमुख व्यक्ति, श्री बुध राम, जिन्होंने दो परिवार शाखाओं के बीच अंतर-लिंक प्रदान किया था, को उस बैंक खाते को संचालित करने के लिए अधिकृत किया गया था। राज्य के अंदर और बाहर पार्टियों के साथ इस घी का कारोबार करने वाली फर्मों के लेन-देन के संबंध में प्रविष्टियां इस बैंक खाते में पोस्ट की गई थीं। बुध राम ने आकलन प्राधिकरण के समक्ष एक बयान भी दिया था, जिसने वादियों को हिसार में घी के कारोबार से जोड़ा था। मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान वादी सहित निर्धारितियों के बयानों और आचरण को अधीनस्थ सिविल न्यायालयों द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। हिसार में सामान्य व्यावसायिक परिसर जिसमें किसी भी अलग हिस्से का विभाजन या सीमांकन नहीं है, घी के टिन के बिना कोई अलग स्टॉक-इन-ट्रेड, आम टिल (नकद या घल्ला), फर्म के नाम के इतने सारे *उपनाम*, फर्म को पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त करने की चूक, दोहराव पुस्तकों की

हरियाणा राज्य, आदि। सावित्रीदेवी और अन्य, (सूर्य, जे)

संख्या, उनमें से कुछ को रोकना और विभिन्न फर्मों के नामों की इन पुस्तकों में प्रविष्टियों को आपस में मिलाना, एक फर्म के नाम पर एक परीक्षण मशीन की खरीद और इन पुस्तकों में परीक्षण शुल्क का दूसरी फर्म को जमा करना, किसी अन्य राज्य में एक स्थान पर रहने वाले वादी द्वारा हिसार स्थित बैंक में खोला गया चालू खाता और इस खाते को संचालित करने का प्राधिकार किसे दिया गया है? वह व्यक्ति जो मालिक या जनरल अटॉर्नी के रूप में पूरे व्यवसाय को स्थानीय रूप से नियंत्रित या प्रबंधित कर रहा था, समय-समय पर उसके द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयान, इन पुस्तकों में सभी वादियों के व्यक्तिगत बही-खातों में निरंतर लेनदेन और मुनाफे को साझा करना, वादी का अनुचित आचरण या विरोधाभास, और पुस्तकों में छिपी हुई या गुप्त भाषा जिसे बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा डिकोड और डिकोड किया जाना था जिन व्यक्तियों से ये खाते संबंधित थे, उनसे कोई भी सहायता के बिना - सभी विनाशकारी सबूत थे जिन्हें किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा तब तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने पहले से ही इस मामले में एक विशेष दृष्टिकोण अपनाने का मन नहीं बना लिया हो। किसी भी मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि आकलन प्राधिकरण, अपीलीय आयुक्त या बिक्री कर न्यायाधिकरण के तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष किसी भी प्रासंगिक साक्ष्य पर आधारित नहीं थे। यह प्रक्रिया की सामान्य प्रक्रिया या अनियमितता से भटकने वाला कोई मामला नहीं है, चाहे वह कितना भी असंगत या महत्वहीन क्यों न हो, जिसे किसी भी मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप न होने के रूप में वर्णित किया जा सकता है ताकि विशेष न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से वंचित किया जा सके या उसके आदेशों को गैर-कानूनी के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। यहां तक कि अगर आकलन प्राधिकरण को साक्ष्य पेश करने या पेश करने के लिए और अवसर देने से इनकार करने में वादी के प्रति कठोर बताया जा सकता है, तो अधिनियम ने "आक्षेपित आदेश" की शुद्धता के खिलाफ अपील या संशोधन में जाकर उस शिकायत को दूर करने के लिए उपाय प्रदान किया था। वास्तव में, अधिकरण या अपीलीय आयुक्तों के आदेशों से यह पता नहीं चलता है कि उनके समक्ष अपीलों की सुनवाई के दौरान इस तरह के किसी भी मुद्दे पर कोई आपत्ति व्यक्त की गई थी। अपील के मेमो में कुछ आधार उठाए जा सकते थे, लेकिन सुनवाई के दौरान इस पर जोर नहीं दिया गया। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि बिक्री कर प्राधिकारी दीवानी मुकदमे में वादी द्वारा चुनौती दिए गए आदेशों को पारित करते समय अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे में रहे हों और सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर स्पष्ट रूप से रोक लगा दी गई थी। इसलिए, राज्य द्वारा दायर नियमित दूसरी अपील संख्या 1972 की 669 सफल होने की हकदार है और वादी-प्रतिवादियों द्वारा दायर मुकदमा खारिज किया जाता है।

हरियाणा राज्य, आदि। सावित्रीदेवी और अन्य, (सूर्य, जे)

(10) यह मुझे राज्य अधिनियम की धारा 22 (2) और केंद्रीय अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत करदाताओं के आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश पर किए गए बिक्री कर संदर्भों पर लाता है।

धारा 22 (1) के तहत अपने आवेदन में करदाता द्वारा निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए गए थे:

(अ) क्या मामले की परिस्थितियों और तथ्यों में, सभी तीन फर्मों की बिक्री:

(एक) मैसर्स बुध राम देसी घी स्टोर,

(दो) मैसर्स. भीम राज बुध राम, और

(तीन) मेसर्स रघुनाथ राय गिरधारी लाल को एक साथ नहीं जोड़ा जा सका और उस पर कर नहीं लगाया जा सका;

(आ) चाहे तथ्यों और परिस्थितियों में और आवेदकों के संबंधों के नाम पर केवल कुछ डेबिट और क्रेडिट के आधार पर सभी को "व्यक्तियों के संघ" का सदस्य घोषित किया जा सकता है और उनके खिलाफ बिक्री कर देनदारियों को फिर से उठाया जा सकता है, उन्हें इसका खंडन करने का उचित अवसर दिए बिना; और

(इ) यदि आवेदकों के विरुद्ध कोई सामग्री नहीं है, तो प्रत्येक मामले में लगाया गया कर और जुर्माना अधिनियम की धारा 6 के तहत बाद के वर्षों में पुस्तकों से निकाले गए निष्कर्ष पर लगाया जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल को मामले को बताने का निर्देश देते हुए इन प्रश्नों को निम्नानुसार संशोधित किया: -

(१) क्या मामले की परिस्थितियों और तथ्यों में, सभी तीन फर्मों की बिक्री:

(एक) मैसर्स बुध राम देसी घी स्टोर,

(दो) मैसर्स. भीम राज बुध राम, और

(तीन) मेसर्स रघुनाथ राय गिरधारी लाल को एक साथ जोड़ा जा सकता है और कर लगाया जा सकता है;

(२) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर बिक्री कर अधिकारी अपने द्वारा तय किए गए "व्यक्तियों के संघ" पर आकलन करने में कानून में सही थे, और

- (३) क्या रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री के बिना विभिन्न वर्षों से संबंधित खातों से निकाले गए अनुमानों और निष्कर्षों पर अधिनियम की धारा 11(6) के तहत प्रत्येक मामले में लगाया गया कर और जुर्माना लगाया जा सकता है?

हरियाणा राज्य, आदि। सावित्री देवी और अन्य (सूरी, जे)

अधिनियम की धारा 11(6) विभिन्न वर्षों से संबंधित लेखाओं से निकाले गए अनुमानों और अनुमानों पर आधारित है।

चूंकि इन्हें कानून के प्रश्नों के रूप में वर्णित किया गया है, इसलिए मुझे केवल यह देखना है कि क्या कर निर्धारण प्राधिकरण, उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त (अपील) और बिक्री कर न्यायाधिकरण के तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष प्रासंगिक साक्ष्य पर आधारित हैं या क्या ये निष्कर्ष किसी भी तरह से विकृत या मूर्खतापूर्ण हैं। मैं पहले ही संक्षेप में उन तथ्यों, परिस्थितियों या सबूतों को संक्षेप में दे चुका हूं जिन पर बिक्री कर प्राधिकारियों की ये धोखाधड़ी आधारित है। भले ही किसी विशेष मामले को साबित करने की जिम्मेदारी विभाग पर थी, मेरे विचार से इस जिम्मेदारी को उन सबूतों द्वारा पूरी तरह से निर्वहन किया गया है जो न केवल प्रासंगिक हैं, बल्कि भारी हैं। निष्कर्ष केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं क्योंकि बुध राम द्वारा मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष दिया गया वक्तव्य इस तथ्य के बावजूद कि वह समय-समय पर अपना पद बदलता रहा है, अनेक विवादास्पद मामलों के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य है। कराधान के मामलों में साक्ष्य के नियम, सबूत की जिम्मेदारी और इसका निर्वहन कैसे किया जा सकता है, यह उन्हीं मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है जो अन्य न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों में प्रचलित हैं और किसी पार्टी या निर्धारिती के गलत या विपरीत आचरण से जो निष्कर्ष या अनुमान निकाले जा सकते हैं, वे एक मामले में दूसरे की तुलना में अलग नहीं होंगे। प्रमाण की जिम्मेदारी ऐसी नहीं है कि इसे केवल एक निर्धारित जादुई मंत्र या मंत्र के जाप से दूर किया जा सकता है / किसी मामले के वैध निष्कर्ष, कानूनी अनुमान या परिस्थितियां इस हद तक स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी को कम कर सकती हैं या सबूत के बोझ को हल्का कर सकती हैं कि संचयी प्रभाव अचानक उस पक्ष के खिलाफ संतुलन को झुका सकता है जिसने अपने झूठे खंडन और आचरण से अपने प्रतिद्वंद्वी को विवाद में एक मामले के सबूत पर डाल दिया था। परिस्थितिजन्य साक्ष्य कुछ और नहीं बल्कि अनुमानों की एक श्रृंखला है, जो मानव आचरण के सामान्य पाठ्यक्रम और कारण और प्रभाव के प्राकृतिक अनुक्रमों को ध्यान में रखते हुए, वैध रूप से मामलों की सिद्ध स्थिति से तैयार किया जा सकता है। न ही यह आवश्यक है कि कराधान मामलों में न्यायालय के फैसले को क्षेत्रीय निरीक्षकों और कराधान विभाग के अन्य अधिकारियों के विभागीय शब्दजाल में रखा जाना चाहिए। *अतुल ग्लास इंडस्ट्रीज, फरीदाबाद बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (17)* के मामले में मेरा अल्पमत का दृष्टिकोण मतभेद के घेरे की विशेषता है, जैसा कि मैं वरिष्ठों के साथ था, लेकिन सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन के ऐसे मामलों के प्रति मेरा दृष्टिकोण बिक्री, कर आयुक्त, मध्य प्रदेश बनाम

एच. एम. एसुफाली, एच. एम. अब्दुलाली, सियागंज, मेन रोड, इंदौर (18) में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों की निम्नलिखित स्पष्ट टिप्पणियों से पूरी तरह से सही साबित होता है:-

(17) (1971) 28 एस.टी.सी. 148.

(18) (1973) 2 एस.सी.सी. 137

- i) " करदाता के खातों के आधार पर किए गए आकलन और 'सर्वोत्तम निर्णय' के आधार पर किए गए मूल्यांकन पूरी तरह से अलग-अलग प्रकार के मूल्यांकन हैं। लेकिन जब आकलन अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि करदाता द्वारा रखे गए खातों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो वह अपने 'सर्वोत्तम निर्णय' के आधार पर करदाता का आकलन करने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसा करने में, वह ऐसी सहायता ले सकता है जो करदाता के खाते वहन कर सकते हैं, वह उसके द्वारा एकत्र की गई अन्य जानकारी के साथ-साथ मामले की आसपास की परिस्थितियों पर भी भरोसा कर सकता है।
- ii) उच्च न्यायालय का यह मानना गलत था कि आकलन प्राधिकारी के पास सटीक कारोबार को साबित करने के लिए सामग्री होनी चाहिए। यदि यह सच है, तो 'सर्वोत्तम निर्णय' मूल्यांकन का कोई औचित्य नहीं है। निर्धारिती को अपने स्वयं के अवैध कृत्यों का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह उनका कर्तव्य था कि वह सभी तथ्यों को सच्चाई से मूल्यांकन प्राधिकारी के सामने रखें। यदि वह अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहता है, तो उसे आकलन प्राधिकारी को निर्णायक रूप से यह साबित करने के लिए बुलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उसने क्या किया था। यह तथ्य उनके 'व्यक्तिगत ज्ञान' के भीतर होना चाहिए। इसलिए उस तथ्य को साबित करने का भार उन पर है। बचे हुए टर्नओवर का पता लगाने में आकलन प्राधिकरण का काम किसी भी तरह से आसान नहीं था। किसी भी बचे हुए कारोबार का अनुमान लगाने में, यह अपरिहार्य है कि कुछ अनुमान-कार्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'सर्वश्रेष्ठ निर्णय' मूल्यांकन करते समय आकलन प्राधिकारी को बिना किसी पूर्वाग्रह के और तर्कसंगत आधार पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचना

चाहिए। वह प्राधिकारी प्रतिशोधी या मनमौजी नहीं होना चाहिए। यदि मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा लगाया गया अनुमान *सच्चा* अनुमान और तर्कसंगत आधार पर आधारित है, यह तथ्य कि उस अनुमान के समर्थन में कोई अच्छा सबूत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। *प्रत्यक्षतः* आकलन प्राधिकारी स्थिति का सबसे अच्छा न्यायाधीश होता है। यह उनका 'सर्वश्रेष्ठ निर्णय' है न कि किसी और का।

- iii) बिक्री कर अधिकारी के पास यह पता लगाने के लिए सामग्री थी कि 19 दिनों की अवधि के दौरान कितना कारोबार आकलन से बच गया था। उस सामग्री के आधार पर उन्होंने पूरे वर्ष के लिए बचे हुए कारोबार का अनुमान लगाया। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि एस.टी.ओ. द्वारा लगाए गए अनुमान का कोई आधार नहीं था। हो सकता है कि उनका अनुमान ओवर एस्टिमेट था या कम एस्टिमेट लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि अनुमान बिना किसी आधार के था। उस अनुमान को बनाने में, अनुमान लगाने का एक तत्व था जो मामले की परिस्थितियों में अपरिहार्य था। यदि एसटीओ को एक नियम अपनाने के लिए मजबूर किया गया था, जो एक अर्थ में एक मनमाना नियम है, तो करदाता उस स्थिति को लाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था।

हरियाणा राज्य, आदि। सावित्री देवी और अन्य (सूरी, जे)

(11) मेरे पास सहमत होने के सभी कारण हैं, भले ही मेरे पास माननीय न्यायाधीशों की इन टिप्पणियों से अन्यथा करने का कोई विकल्प हो।

(12) मोहम्मद नूरुल्ला, स्वर्गीय खान साहब मोहम्मद उमर साहब की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं बनाम आयकर आयुक्त, मद्रास (15) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपात के भीतर अपने परिवारों के अन्य सदस्यों के साथ सह-साहसी के रूप में वादी के एकजुट होने के सबूत सामने आए हैं और यह आवश्यक नहीं था कि बैंड में नियमित साझेदारी के सभी लक्षण होने चाहिए थे। सदस्य आम तौर पर भागीदारों द्वारा पालन की जाने वाली किसी भी औपचारिकता के बिना व्यक्तियों के बैंड या एसोसिएशन में शामिल हो सकते हैं या हट सकते हैं, जैसा कि *जी मुरुगेसन एंड ब्रदर्स बनाम आयकर आयुक्त, मद्रास (19) में सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले से प्रतीत हो सकता है*। इस संबंध में श्री दीवान द्वारा जिन अन्य विनिर्णयों पर भरोसा किया गया है उनमें *आयकर आयुक्त/बॉम्बे, उत्तरी कच्छ और सौराष्ट्र, अहमदाबाद बनाम श्रीमती इंदिरा बालकृष्ण (16) और आयकर आयुक्त, पूना बनाम बुलढाणा जिला मुख्य कपड़ा आयातक समूह (14)* शामिल हैं। । निस्संदेह, यह न्यायालय साक्ष्य की प्रासंगिकता या स्वीकार्यता के प्रश्न पर विचार कर सकता है, लेकिन वह कराधान प्राधिकारियों के तथ्यों के निष्कर्षों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए इसकी पर्याप्तता के प्रश्न पर विचार नहीं कर सकता है। जबकि साक्ष्य का विश्लेषण देखने के विचार के साथ - क्या यह 'पहले परीक्षण को संतुष्ट करता है' को कानून के प्रश्न के रूप में वर्णित किया जा सकता है, इस सबूत का भौतिक वजन यह देखने के विचार के साथ कि यह संतुलन को एक या दूसरे के पक्ष में झुकाता है या नहीं।

पार्टी तथ्य का प्रश्न होगा। इस न्यायालय को यह भी देखना है कि क्या संतुलन रखने वाला हाथ एक पक्ष के पक्ष में और दूसरे पक्ष के खिलाफ संतुलन को झुकाने की बेईमानी से कोशिश नहीं कर रहा है।

- (13) ऊपर दिए गए कारणों के लिए, प्रश्न संख्या (i) के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किया गया उत्तर हां में दिया गया है, अर्थात् राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के खिलाफ।
- (14) प्रश्न संख्या (ii) का उत्तर इसी प्रकार हां में दिया गया है, अर्थात् राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के विरुद्ध।
- (15) प्रश्न संख्या (iii) का उत्तर यह है कि विभाग द्वारा संगत साक्ष्य के आधार पर और वादी सहित करदाताओं के असहयोगात्मक रवैये को ध्यान में रखते हुए अनुमान या निष्कर्ष वैध रूप से निकाले गए थे और यह कि सभी मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रत्येक मामले में लगाया गया कर और जुर्माना उचित था। यह नहीं कहा जा सकता है कि ये आकलन रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री के बिना किए गए थे। लगाए जाने वाले जुर्माने की मात्रा आकलन प्राधिकारी के विवेकाधिकार के अंतर्गत आने वाला मामला है और उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित करने के लिए कोई संदर्भ नहीं मांगा जा सकता है कि लगाए गए जुर्माने की राशि अत्यधिक है या नहीं, जैसा कि इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा *नेशनल मोटर्स बनाम पंजाब राज्य (20)* मामले में कहा गया था।
- (16) ऊपर दिए गए कारणों के लिए, 1972 की नियमित दूसरी
- (20) (1971) 28 एस.टी.सी. 442

अपील संख्या 669 को स्वीकार किया जाता है और नीचे दिए गए सिविल न्यायालयों के निर्णयों और डिक्री को रद्द कर दिया जाता है। व्यक्तियों के संघ के कुछ सदस्यों द्वारा दायर मुकदमा, जिन्हें कर और दंड के लिए मूल्यांकन किया गया है, खारिज कर दिया जाता है। इस न्यायालय को भेजे गए सभी तीन प्रश्नों का उत्तर राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के खिलाफ दिया गया है। पार्टियों को अपनी लागतों को वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

पंडित, जे- मैं अपने विद्वान भाई द्वारा प्रस्तावित आदेश से सहमत हूँ।

के.एस.के.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आशिमा गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
गुरूग्राम, हरियाणा

